



2026:AHC:62732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10156 / 2026

नवाब

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : आदर्श त्रिपाठी, अविनाश त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री अविनाश त्रिपाठी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राकेश कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 1794 / 2017, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- इन्द्रापुरम, जनपद- गाजियाबाद से संबंधित प्रकरण में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को केवल एक आधारभूत मामले के आधार पर मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदित किया गया है कि आवेदक को आधारभूत मामले, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 40 वर्ष 2015 में पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। जिसकी प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथ-पत्र में अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। इसलिए आवेदक इस प्रकरण में भी जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त, आवेदक दो अन्य प्रकरणों में संलिप्त था, जिनमें उसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जिनकी प्रतियाँ जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथ-पत्र में अनुलग्नक-3 और 4 के रूप में संलग्न हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षीय पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और 19.01.2018 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, परंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक प्रकरणों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए एवं **2025 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 3038** में प्रकाशित **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और प्रकरण की योग्यता पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

6. आवेदक- **नवाब**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ न करे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए विचारण / अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. संबंधित न्यायालय मुचलके स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जमानत प्रदान किए जाने हेतु नीतिगत रणनीति के संबंध में, स्वप्रेरणा से दायर रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में पारित आदेश, दिनांक 31.01.2023, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 मार्च, 2026

एस.ए/-

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।